

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेष्य,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 30 सितम्बर, 2009

विषय : विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में Defect Liability Period तथा
अनुरक्षण अनुबन्ध सम्बन्धी प्राविधान।

महोदय,

पूँजीगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से अनुरक्षण हेतु प्राविधान करने तथा Defect Liability Period निर्धारित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल तत्काल प्रभाव से निम्न स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:--

1. प्रदेश के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत समस्त पूँजीगत परियोजनाओं हेतु Defect Liability Period 01 वर्ष निर्धारित किया जाता है। तदनुसार समस्त विभागों द्वारा निर्माण अनुबन्ध (Construction Agreement) में ही इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा और समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा Defect Liability हेतु संविदा का कड़ाई से Enforcement सुनिश्चित किया जाएगा।
2. मार्गों/सड़कों के सम्बन्ध में निर्माण अनुबन्ध में ही अनुरक्षण अनुबन्ध की अवधि 03 वर्ष निर्धारित की जाती है। प्रत्येक अनुरक्षण अनुबन्ध Defect Liability Period के साथ ही प्रभावी होगा। यह अनुरक्षण अनुबन्ध डामरीकरण के साथ पूर्ण किए जाने वाले सड़क निर्माण कार्य एवं ऐसे सड़क निर्माण कार्यों पर भी प्रभावी होगा, जिसके फलस्वरूप निर्मित मार्ग पर सार्वजनिक यातायात विधिवत चालू हो जाए।
3. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था बनाई जाती है। प्रथम स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था कार्यदायी संस्था अर्थात् जिस निर्माण संस्था द्वारा निर्माण कार्य कराया जाए, उसके विभाग के स्तर पर बनायी जाएगी तथा द्वितीय स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था उस प्रशासकीय विभाग के स्तर पर बनाई जाएगी जिसका निर्माण कार्य कराया जाना हो। तृतीय स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था नियोजन विभाग के स्तर पर बनाई जाएगी।

समस्त विभाग उपर्युक्तानुसार निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से एक एजेंड का सठन करेंगे तथा निर्माण कार्यो का निरन्तर अनुश्रवण कर प्रसिद्ध आधार पर नियोजन विभाग को अवगत कराया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव।

संख्या : १२ / XXVI/एक(11)/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
9. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण को मा0 मंत्रीगण के सूचनार्थ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गाई फाइल।

12. एन० आर्डी० सी० सचिवालय परिसर, दे० पू० 1

आज्ञा से,


(रामा रतूड़ी)
सचिव।